

## उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये नरियात पर ज़ोर

### चर्चा में क्यों?

24 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दशा में नरियात बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है तथा इसके तहत कार्ययोजना बनाकर काम शुरू कर दिया गया है।

### प्रमुख बंदि

- प्रवक्ता ने बताया कि नरियात पिछले साल के 21 लाख करोड़ रुपए से 30 प्रतिशत बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सरकार का लक्ष्य अगले तीन साल में इस आँकड़े को 2 लाख करोड़ रुपए करने का है।
- उन्होंने कहा कि यह पहचानने का प्रयास किया गया है कि किन उत्पादों में नरियात की संभावनाएँ हैं, किस ज़िले में कौन-से प्रमुख उत्पाद हैं आदि। राज्य स्तर पर ऐसे 15 सेक्टरों का चयन किया गया है। जिन उत्पादों का नरियात किया गया है, उनके अलावा उन उत्पादों की भी पहचान की गई है, जिन्हें थोड़े और प्रयास से नरियात योग्य बनाया जा सकता है।
- हर ज़िले में ज़िला नरियात योजना पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही डीएम की अध्यक्षता में ज़िला नरियात समितियों का भी गठन किया गया है। हर महीने एक बैठक होगी और वभाग को स्थानीय स्तर पर नरियातकों के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत कराया जाएगा।
- एमएसएमई (MSME) वभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि नरियातकों को वदेशी खरीदारों के साथ सीधे जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा वदेशों में आयोजित होने वाले मेलों और प्रदर्शनियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रदेश के नरियातकों को वदेश में लगने वाले मेलों और प्रदर्शनियों में भेजने की भी योजना बनाई गई है।
- एमएसएमई वभाग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी, वाहन और वाहन उपकरण, रतन और आभूषण, कार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात लेख, परधान (साड़ी सहित), फर्नीचर, चमड़े और चमड़े के उत्पाद, खेल के सामान, काँच और काँच के बने पदार्थ, इत्र, सरिमिकि, कालीन और हस्तशिल्प क्षेत्र से संबंधित है।
- प्रवक्ता ने कहा कि प्रोजेक्ट 'वन डिसिंक्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी)' नरियात में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। अन्य देशों के दूतावासों में भी सरकार द्वारा ओडीओपी की ब्रांडिंग की जाएगी। ओडीओपी उत्पादों को दूतावासों में भी प्रदर्शित किया जाएगा। नरियात बढ़ाने के लिये उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने नरियात को बढ़ावा देने के लिये इस वर्ष 'उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम' के बजट को दोगुना कर दिया है। इस योजना के लिये 7 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसी तरह 'त्वरित नरियात विकास प्रोत्साहन योजना' के तहत सब्सिडी देने के लिये इस वर्ष बजट को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है।